[k.M% 3] vad% 02 Qjojh 2020

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

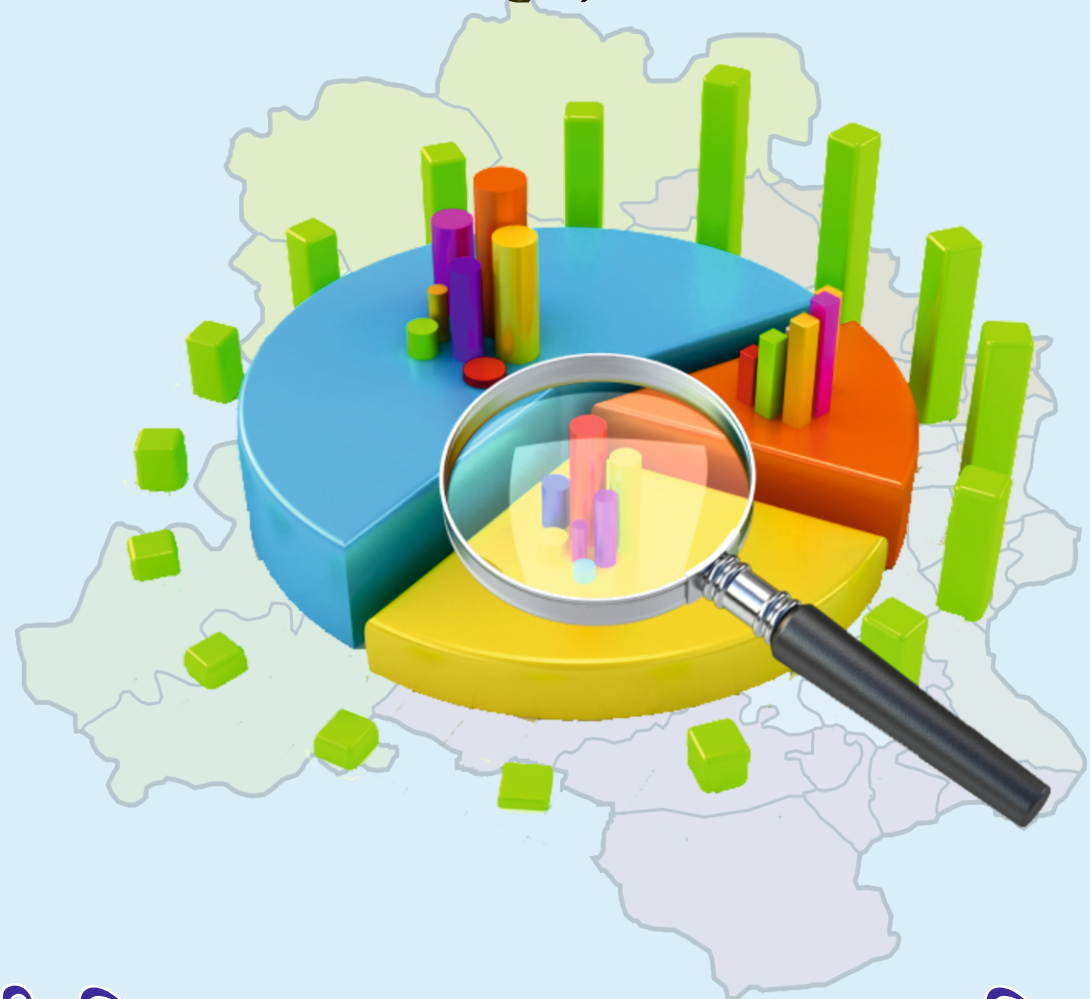

दिल्ली विधान सभा चुनाव, 2020: एक विश्लेषण

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2020

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

दिल्ली विधान सभा चुनाव, 2020: एक विश्लेषण

अनुक्रमिका

संपादकीय i-ii

1. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020: एक विश्लेषण – मधु यादव 1–3

2. दिल्ली विधानसभा चुनाव: मुद्दों की राजनीति – राखी 4–6

3. दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020: भारतीय चुनाव में सकारात्मक राजनीति 7–9
– नवीन कुमार

4. दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020: राष्ट्रीय बनाम स्थानीय विषयों की राजनीति 10–12
– राम किशोर

5. दिल्ली विधान सभा चुनाव 2020: विकास बनाम सांप्रदायिकता? – काजल 13–15

6. दिल्ली विधान सभा चुनाव, 2020: एक नारीवादी विश्लेषण – मधु झा 16–18

7. राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी: राम बनाम हनुमान की राजनीति 19–21
– जया ओझा

सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित एवं सम्रपित शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के निरंतर सहयोग से एक बार पुनः हम केन्द्र की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के वर्ष 2020 के इस द्वितीय अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित कर रहे हैं। संश्लेषण का प्रत्येक अंश उस माह की ज्वलंत वास्तविकता एवं समसामयिकता को एक निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ रुप से प्रकट करने का हमारा एक न्याय्य प्रयास है।

वर्ष 2020 का शुभारंभ भारत की राज्यीय राजनीति तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक नव परीक्षण एवं निरीक्षण के रुप में अभिव्यक्त हुआ। गत वर्ष महाराष्ट्र, हरियाणा तथा झारखण्ड़ के चुनाव परीणामों के पश्चात फरवरी 2020 भारत की राजधानी दिल्ली के राजनीतिक भाग्य निर्णय की परीक्षा का माह रहा। उपरोक्त तीन राज्यों में अपनी शानदार सफलता की पुनरावृत्ति की कमी को दिल्ली क राजनीतिक मंच पर कारगर सफलता के रुप में स्थापित करने के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधान सभा के चुनाव को 'करो या मरो' की संज्ञा सहित लिया। वहीं पांच वर्ष पूर्व अपनी अभूतपूर्व चुनावी सफलता अभियान को विजयी रथ सहित एक बार पुनः दिल्ली की विधान सभा पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आम आदमी पार्टी ने सुशासन एवं प्रलोभन के मध्य एक विशिष्ट संतुलन बनाकर प्रचार–प्रसार के प्रत्येक अवसर का इस चुनाव में महत्वपूर्ण प्रयोग किया। दिल्ली विधान सभा के चुनावी परिणाम में आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत ने समस्त चुनावी विश्लेषज्ञों एवं पंडितों सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं की संकल्पनाओं एवं संभावनाओं को विफल कर दिया।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'दिल्ली विधान सभा चुनाव, 2020: एक विश्लेषण' विषय पर लेख आमंत्रित किये। सात उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख दिल्ली विधान सभा के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने के साथ–साथ दिल्ली के मतदाता की परिवर्तनीय प्रकृति के भी अध्ययन का एक विनीत प्रयत्न है।

संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ राजधानी दिल्ली से संबद्ध सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के विविध आधारभूत बिंदुओं को भी प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को

संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदशित करते हैं।

वर्ष 2020 के संश्लेषण के इस फरवरी माह के द्वितीय अंक मं प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हम मार्च माह के अपने तृतीय समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

मंगलवार, 14 अप्रैल 2020

1

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020: एक विश्लेषण

मधु यादव

परास्नातक, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में चुनावी राजनीति में मतदाता व्यवहार में परिवर्तन कि एक झलक दिखाई देती है। बीसवीं सदी में चुनावी राजनीति की उठा–पटक के बीच मतदाता व्यवहार का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। मत व्यवहार का अध्ययन सर्वप्रथम 1913 में फ्रांस द्वारा किया गया। मूलतः मतदाता व्यवहार से अभिप्राय है कि वह कौन से तत्व है जिन से प्रभावित होकर मतदाता अपने नेता व शासनकता को चुनता है। वास्तव में मत व्यवहार ही राजनीति का आधार है, जिसमें लोकप्रिय संप्रभुता निवास करती है। जो किसी भी शासन व्यवस्था को वैधता प्रदान करती हैं। हालांकि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल मत व्यवहार को प्रभावित करने के कई प्रयास करते हैं। लेकिन मत व्यवहार किसो भी राजनीतिक दल के समर्थन और विरोध में एक व्यक्तिगत निर्णय है।

ठीक इसीप्रकार, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में धर्म, जाति, वर्ग की राजनीति के विपरीत विकास और मुद्दों की राजनीति को विजय प्राप्त हुई। यह पहला अवसर था जिसमें किसी दल ने विकास के मुद्दों के आधार पर राजनीति की पहल की थी। मतदाता व्यवहार सामान्यता मूल रूप से चार बिंदुओं (1) विकास (2) विचारधारा (3) नेतृत्व (4) मुद्दों से प्रभावित होते हैं। हालांकि इसी के अतंर्गत केंद्रोय सरकार द्वारा धारा 370 को हटाया जाना और सी. ए. ए. जैसे विषय से भी गर्मजोशी का वातावरण बना रहा। लेकिन केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा का यह विषय आम जनता को आकर्षित नहीं कर पाया।

2020 के चुनाव घोषणा पत्रों में राजनीतिक दलों ने विभिन्न प्रलोभनयुक्त मुद्दों तथा धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने का प्रयास भी किए गए। हिंदू, मुस्लिम, वर्ग, जाति, और लिंग की राजनीति के विपरीत आम आदमी पार्टी ने सामाजिक कल्याणकारी कार्यों, मुद्दों आदि पर आधारित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा, पानी, बिजली तथा यातायात साधन के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार के कार्य किए। सरकार द्वारा किए गए

प्रशासनिक सुधारों ने दिल्ली के परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत मत को प्रभावित किया। 2020 के चुनावी सर्वेक्षण के अतंर्गत यह पाया गया कि इस विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सूची व्यवहार में कई प्रकार से परिवर्तन आए हैं, जैसे वह लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही दल को वोट करते आ रहे थे, वह भी अब सरकार के कार्यों को देखकर वोट कर रहे है, आम नागरिको में यह समझ विकसित हो गई है की केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के लिए किस दल का शासन बेहतर होगा तथा किस दल को कहां पर चुना जाना चाहिए। जैसा कि प्रमाणित है कि दिल्ली में अधिकतर जनसंख्या प्रवासियों की है जहां लोग रोजगार की खोज में दिल्ली की ओर रुख करते हैं, ऐसे परिवारों के लिए महंगाई के इस दौर में बच्चों का पालन–पोषण, बेहतर शिक्षा, स्वच्छ जल, बढ़ती बिजली के दाम आदि चिंता का एक विषय बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने पिछले 5 सालों के कार्यकाल में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति, मुफ्त शिक्षा, पेरेंट्स मीटिंग तथा नए स्कूलों में कक्षाओं का निर्माण, पुरानी बिल्डिंग में सुधार करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया तथा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यों की रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करते हुए बच्चों के माध्यम से परिवार तक पहुंचने का प्रयास किया। इस प्रकार गरीब परिवारों का मतदाता व्यवहार कांग्रेस और बीजेपी की दलों के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी इस तरफ बढ़ा, दूसरी ओर आम आदमी सरकार ने अपने ही कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए डीटीसी (दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) मेरी यात्रा की व्यवस्था कर दी। परिणामस्वरूप कुल मत का 50 प्रतिशत वोट अर्थात महिलाआं के मत व्यवहार में परिवर्तन आया तथा आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ा।

इस प्रकार दिल्ली सरकार ने नीचले स्तर पर उतर कर नागरिकों की मूल आवश्यकताओं को लक्ष्य बनाकर नागरिकों की पसंद को अपनी ओर प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित किया। वास्तव में, किसी भी सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्य नागरिकों के निरंतर चलने वाले जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते जबकि आम आदमो सरकार द्वारा चलाए गए एजेंडें नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े विषय को प्रभावित करने की राजनीति थी। अंततः आम आदमी पार्टी की सरकार ने व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक तौर पर परिवारों के मत रुझानों में परिवर्तन की राजनीति की, क्योंकि किसी भी परिवार में महिला व बच्चों का विकास महत्वपूर्ण होता है और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा की गई इस प्रकार की नीतियों ने परिवारों को भावनात्मक रूप से भी सोचने पर विवश किया और दूसरी ओर परिवार के पुरुषों के मत निर्णयों को भी अपनी और आकर्षित किया।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीति के इस नए स्वरूप में मतदाता व्यवहार की मानसिकता व पसंद को परिवर्तित करके मतदाताओं को धर्म, राजनीति से विपरीत नए ढंग से सोचने के विचार को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दूसरी ओर जिस प्रकार दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों ने धर्मों के बीच में फूट डालने के प्रयास किए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है भारत जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है उसे दीमक लग गया हो। यहां सभी दलों ने अपने–अपने वोट बैंक के लिए एक धर्म और जाति को अपनी राजनीतिक पहचान दे दी है, जिसने लोकतंत्र के मूल्यों को आंतरिक रूप से खोखला कर दिया है।

परंतु, इस विधानसभा चुनाव में महात्मा गांधी जी के लोकतंत्र की परिभाषा की सिद्धि दिखाई देती हैं जैसा कि गांधी जी कहते हैं, 'मैं (गांधी) समझता हूं कि राजनीति को सामाजिक और नैतिक कार्यों की प्रगति के संदर्भ में देखना चाहिए।' अंतः यह आवश्यक है कि दलों के बीच प्रतियोगिता के दौर में धर्म और जाति की राजनीति को छोड़कर सामाजिक कल्याण और विकास की राजनीति पर बल दिया जाए।

निष्कर्षः 2020 विधानसभा चुनाव में वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्य की स्वासिद्धि दिखाई देते हैं। तथा फेरबदल की दलगत राजनीति, धर्म, जाति, लिंग और दलीय विचारधारा की राजनीति के विपरीत विकास और मुद्दों की राजनीति को विजय प्राप्त हुई। यह पहला अवसर था, जहां गंदी राजनीति की अपेक्षा समाज के लिए कल्याणकारी कार्य किए गए। आम नागरिकों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया गया। इस प्रकार वास्तविक लोकतंत्र को जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाया जाए और जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और लिंग आदि कारकों को मतदाता व्यवहार पर हावी होने से रोका जाए। अंत यह आवश्यक है, कि जनता के बीच भ्रम व लोभ के बजाय जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए।

♦♦♦♦♦

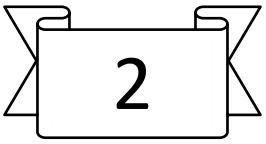

दिल्ली विधानसभा चुनावः मुद्दों की राजनीति

राखी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता दल तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के प्रदर्शन ने ऐतिहासिक रूप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लाभ से अधिक इन दलों की छवि को आघात पहुंचाया है। भारतीय जनता दल ने केवल 8 सीटों पर अपनी जीत हासिल की जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में दो बड़ राष्ट्रीय दलों के प्रदर्शन तथा इनके सिमटते मत प्रतिशत न इन दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा झटका दिया ह। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे न केवल स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ा गया बल्कि भारतोय राजनीति के अहम मुद्दों से भी यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की आशंका रही है।

दिल्ली में सरकार बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लगातार दिल्ली वालों की किसी एक दल को निरंतर समर्थन करने की उस परंपरा को निभाया है जा भारतीय जनता दल तथा कांग्रेस को लगातार दिल्ली में जीत से बनी थी। जिस प्रकार ये दोनों दल लगातार दो से तीन बार निरंतर जीत हासिल करके सत्ता हथियाने में कामयाब रहे थे उसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने भी लगातार हुई तीसरी जीत में यह सिद्ध कर दिया है कि यहां पार्टी का प्रदर्शन राष्ट्रीय मुद्दों स हटकर आम जनमानस के हितों से संबंधित मुद्दों को उठाकर ही यहां शासन कर पाना संभव होगा।

द्विदलीय राजनीति में नेतृत्व का प्रभाव

पिछले तीन चुनावों से दिल्ली में द्विदलीय प्रभुत्त्व के सिद्धांत में परिवर्तन हुआ है जिससे आम आदमी पार्टी को बेशक बाहर के राज्यों में मतदाताआं ने पसंद ना किया हो किंतु यहाँ के मतदाताओं ने इन्हें भारी बहुमत से जीता कर यह साबित किया है कि दिल्ली में इस पार्टी का भविष्य अभी और गढ़ना बाकी है। परंतु जो एक प्रवृत्ति यहाँ पर निरंतर देखी गयी की मुख्यमंत्री के लिए चेहरा तथा पार्टी में उसकी स्थिति सदैव ऐतिहासिक रूप से इस राज्य की राजनीति को

प्रभावित करती है। इस विषय में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तथा पार्टी में उनके अन्य व्यक्तियों को पछाड़ते हुए मजबूत स्थिति बनाना या आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की एक मजबूत स्थिति का निर्माण हो दोनों होना इस प्रदेश की राजनीति में मतदाताओं को प्रभावित करने में एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

यह प्रदर्शित करता है कि नेतृत्व द्वारा प्रदर्शित विकास मार्ग का मुद्दा यहां के मतदाताओं के लिए सर्वप्रथम तथा सर्वमान्य है। जिसने इन तीनों दलों में एक सामान्य विशेषता को बल दिया जो थी कार्य के आधार पर एक दल को लगातार सत्ता में बैठाना तथा उनके कार्यों के आधार पर ही मतदाताओं द्वारा उस दल को हटाकर दूसरे दल को सत्ता प्रदान करना। इससे निरंतर एक दल का दो से तीन बार लगातार सत्ता में कार्यकाल के लिए बने रहना सरल बन गया, जैसा कि 1993 से 1998 भारतीय जनता दल की सरकार, 1998 से 2013 तक कांग्रेस तथा इसके पश्चात् 2013 से 2014 में लगे राष्ट्रपति शासन के साथ वर्तमान तक आम आदमी पार्टी की सरकार यहां बनी रही एक ही सरकार की निरंतरता ने राज्य की राजनीति में एक नये आयाम को लागू रखा हैं जिसके अनुसार किसी भी दल का सत्ता से जाना उसके जनसंपर्क में कमी का मुख्य परिणाम माना जा सकता है।

दिल्ली विकास कार्यक्रम– द्विदलीय से एक दल प्रभुत्व में बदलती राजनीति

1980 के दशक में दो ध्रुवीय राजनीति ने मुद्दों और विचारधाराओं के अंतर को मिटा दिया किंतु मदन लाल खुराना तथा हरी किशन लाल भगत के नेतृत्व में चली राजनीति में दो ध्रुवों के मध्य की राजनीति बढ़ी। जिससे मुद्दों तथा रणनीतियों का अंतर सिमटता चला गया। हिंदी की राजनीति तथा 1984 के दंगे भी मतदाताओं पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सके। इन परिस्थितियों के आधार पर 1997 के चुनाव प्याज के मूल्य जैसे छोटे मुद्दों पर लड़े गए हालाँकि मंदिर मंडल जैसे मुद्दों पर विरोध यही से आरंभ हुआ। किन्तु उसके पश्चात् भी यहाँ की राजनीति में इन विषयों से अधिक बदलाव नहीं दिखे, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित के कार्यो के आधार पर अलग पहचान गढ़ने में सफल रही जिसने पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों को पछाड़ दिया।

दिल्ली में व्यक्ति विकास के मुद्दे पर एकीकृत होकर 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए तीसरी बार विजय का आधार बना। इस प्रकार भारतीय राजनीति के प्रभावी जन संपर्क संबंधी

मुद्दों से अलग चुनाव में भारतीय जनता दल को विपक्ष का अधिक प्रभावी विरोध ना मिलने के कारण इन चुनावों में भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई । केजरीवाल सरकार के भारतीय राजनीति में हो रहे उथल–पुथल के पश्चात भी इनकी रणनोतियों में स्थानीय विकास तथा जनसामान्य को प्रभावित करने वाले मुद्दे महत्त्वपूर्ण थे जो राजनीतिक लाभ हेतु समय–समय पर परिवर्तित अवश्य हुए। जिसने शाहीनबाग मुद्दे को शामिल कर इसे धर्म के विवाद में शामिल करने की कोशिश की गई, किंतु यह मुद्दा स्थानोय मुद्दों से अधिक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। केजरीवाल ने स्थानीय मुद्दों जैसे शिक्षा, बिजली, पानी तथा स्वास्थ्य के मुद्दों से जोड़कर इसे विकास का मुद्दा बना विजय हासिल की। इसके अलावा निरंतर जनसामान्य में साधारण वर्ग के दैनिक के मुद्दों को अपन घोषणा पत्र में शामिल कर नेतृत्व ने स्वयं को सदैव निम्न वर्ग से जोड़कर इनके मुद्दों को सम्बोधित कर अपने एजेंडे में रखा, जिसका लाभ इस दल को स्पष्ट रूप से इन दोनों चुनावों में मिला तथा जनता के मध्य यह अपनी छवि जनहित के लिए अग्रसर रहने वाली पार्टी के रूप में बना पाई है।

निष्कर्ष

इससे यह प्रदर्शित हुआ क्या आम आदमी पार्टी एक प्रभावी पार्टी बन नये संस्थागत बल के रूप में उभरी है, जिसने बिना किसी गठजोड़ के पुनः राष्ट्रीय दलों को गंभीर चुनौती दी है। दूसरा क्या यह राष्ट्रीय दल इतने प्रभावी दल को प्रतिस्पर्धा देकर दोबारा अपना स्थान प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे? क्योंकि भारतीय जनता दल लोकसभा चुनाव में 50% मत प्राप्त करने के पश्चात भी अधिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। साथ ही मुख्यमंत्री पद की अनुपस्थिति ने इसके समक्ष अन्य समस्या पैदा की है उसका लाभ भी आम आदमी पार्टी को मिला। हालांकि दोनों दलों के मध्य यह सीटों का अंतर मत प्रतिशतता में नहीं दिखता क्योंकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों के साथ 53.6 प्रतिशत तथा भारतीय जनता दल को 8 सीटों के साथ 38.5% मत प्राप्त हुए। जिनसे प्रदर्शित होता है कि दोनों के मध्य सीटों का अंतर मत प्रतिशतता में नहीं है जो पिछले चुनाव की तुलना में आम आदमी पार्टी में कम हुआ है तथा भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। परंतु इसके पश्चात 2020 के चुनाव ने भारतीय राजनीति में कुछ नए आयामों को उभरने का अवसर प्रदान किया।

♦♦♦♦♦

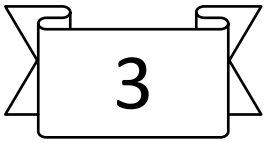

दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020: भारतीय चुनाव में सकारात्मक राजनीति

नवीन कुमार

परास्नातक, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 को कई मायनों में एक महत्त्वपूर्ण चुनाव माना जा सकता हैं। एक ऐसे दौर में दिल्ली का चुनाव हुआ है जब भारतीय चुनाव संस्कृति में सांप्रदायिकता का बीज बोया जा रहा है। हमने 2019 में महाराष्ट्र, झारखण्ड, हरियाणा की विधानसभा चुनावों में देखा है कि किस प्रकार से स्थानीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा हावी था। लेकिन, दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया हैं कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीन मुख्य पार्टियां थी। जिसमें मुकाबला सिर्फ. आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिला। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। पर हम यह नहीं कह सकते कि दूसरी पार्टी की हार हुई है। क्योंकि, बीजेपी जिस विचारधारा के साथ इस चुनाव को लड़ रही थीं उसमें उसको हार के बाद भी जीती हुआ पार्टी मान सकते है। क्योंकि, बीजेपी की हिन्दुत्व वाली राजनीति को अरविंद केजरीवाल हरा नहीं पाए।

वैसे भारत में चुनावो परंपरा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, मतदाता के व्यवहार को समझना। लेकिन, पिछले कुछ चुनावों से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में मतदाता के व्यवहार को बदलने के लिए नए–नए हथकंडे अपनाएं जाने लगे है। जिसके कारण अब हम जब भी किसी चुनाव का विश्लेषण करते है तब हमें कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 का विश्लेषण कई तरह से किया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली के मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा प्राथमिकता दी? दूसरा, राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को लेकर बनाई रणनीति में कहां असफल हुए? इसके अलावा दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की कौन–सी योजना अच्छी लगी, जिसके कारण दिल्ली की मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को 70 सीटो वाली दिल्ली विधानसभा में से 62 सीटें जीता दी? ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण किया जा सकता है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह साफ देखने को मिलता है कि जनता ने विकास की राजनीति को पसंद किया है। और तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्रो बनाया। पर क्या दिल्ली के चुनाव में सिर्फ विकास की बात हुई, ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, उसमें वह हार कर भी जीत गई। हिंदुत्व की जिस राजनीति को अरविन्द केजरीवाल अपने शुरुआती राजनीति जीवन में विरोध कर रहे थे, इस चुनाव में उनको "जय बजरंग बली" बोलने तक ले आया। इस चुनाव को जिस तरह से बीजेपी के द्वारा राष्ट्रवादी चुनाव बनाया गया, उसमें कहीं–न–कहीं आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी सभा को एन्टी–मोदी होने से बचाया। और बीजेपी जिस शाहीन बाग को इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाने में लगी रहीं, उस पर भी आम आदमी पार्टी के नेता बोलने से बचते रहे। इसके अलावा, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया पिछले पांच साल के कार्य ने भी दिल्ली के मतदाताओं को विशेषरूप से प्रभावित किया।

बिजली, डीटीसी बस में महिलाओं के लिये मुफ्त सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक जैसी सुविधाओं ने इस चुनाव में मध्य आय वाले परिवार को अधिक प्रभावित किया। जिससे कारण, आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाई। दिल्ली के मध्यम वर्ग के परिवार को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, सस्ती और अच्छी शिक्षा और बिजली–पानी मुफ्त हो जाना कई रूप से उनके दिनचर्या के खर्चो को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसका परिणाम आम आदमी पार्टी को 62 सीटों के रूप में मिला।

हम जानते है कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से शाहीन बाग बनाव विकास पर लड़ा गया। शाहीन बाग की बात बीजेपी के नेता कर रहे थे वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के चुनाव मं स्थानीय मुद्दे पर बात करते रहे। वह केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई नागरिकता कानून, 2019 पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। इसके अलावा, इस चुनाव में एक विशेष समुदाय को आतंकवादी बताने का प्रयास होता रहा। बीजेपी के कुछ नेताओं ने अमर्यादित बयान दिया, जिसका बीजेपी के कुछ नेताओं ने विरोध किया और कहा कि नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो इस चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का पूरा प्रयास किया गया। जिसका परिणाम चुनाव के बाद दिल्ली के नार्थ–ईस्ट दिल्ली दंगे के रूप में देखने को मिला। इसके अलावा, शाहीन बाग और जामिया नगर में गोली चलने से यह पूरी तरह से साफ हो गया कि भारत के नेताओं ने चुनाव में किस प्रकार से साम्प्रदायिक सद्भाव को खराब करने का प्रयास करते हं। नेताओं के लिए चुनाव महत्व रखते है उसमें भाग लेने वाली जनता

नहीं। भारतीय चुनाव संस्कृति में यह माना जाता है कि कार्य की राजनीति पर चुनाव जीतना कठिन है। पर दिल्ली के चुनाव ने काफी हद तक इस धारणा को तोड़ दिया है। इसने कार्य की राजनीति को एक नया नाम दिया है जिसका प्रभाव आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। नेताओं को यह समझना होगा कि सकारात्मक राजनीति करके भी चुनाव जीता जा सकता है। हर चुनाव में घृणा फैला के चुनाव जीत तो जाते है पर चुनाव की संस्कृति पर एक दाग–धब्बा लगा देते है जिसको मिटाना, उस समय के लिए कठिन होता हैं। इसलिए, यह आवश्यक हैं कि सकारात्मक राजनीति की जाए और किसी भी चुनाव को कार्य–विकास पर लड़ा जाए। जिससे जनता की भलाई होगी। चाहे कोई भी दल चुनाव जीते। अंत में लाभ जनता का होगा। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव सकारात्मक राजनीति पर लड़ा जाए और जिसकी शुरुआत काफी कुछ खोने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखने को मिला है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव ने एक नए राजनीति को जन्म दिया है। जिसमें राष्ट्रवाद क साथ–साथ काम की राजनीति को प्रमुखता से उठाया गया। और जिस मुद्दे पर बीजेपी पिछले 40 वर्षो से बात कर रहो है उसकी पहली सफलता हार थी। जिस आम आदमी पार्टी को 2015 के चुनाव में सेंटर–लेफ्ट विंग वाली पार्टी कहा जाता था।

आज, उसको सेन्टर–राइट विंग वाली पार्टी कहा जाने लगा। जिसका उदाहरण, आम आदमी पार्टी ने "जय बजरंग बली" जैसी नारों से दिया और अरविंद केजरीवाल द्वारा इस पूरे चुनाव में मोदो सरकार को लेकर अपनाया गया कोमल नजरिया यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल अब उस प्रकार की राजनीति नहीं कर रहे है जिसको शुरुआत उन्होंने 2013 में की थी। अंत में, यह कहा जाना कठिन है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत जनता की हुई या किसी विशेष पार्टी की, जो अगले पांच साल तक अपनी सरकार बनाये रखेगी

♦♦♦♦♦

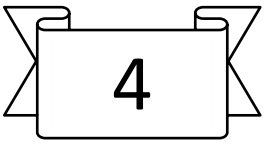

दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020: राष्ट्रीय बनाम स्थानीय विषयों की राजनीति

राम किशोर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली के विधान सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार पुनः ऐतिहासिक बहुमत मिला है। दिल्ली विधान सभा की 70 सीटों में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 70 सीटों में से 8 सीटें प्राप्त हुई है। अत्यधिक प्रयासों के पश्चात भी भाजपा को 8 सीटो से ज्यादा प्राप्त नहीं हुई हैं। कांग्रेस की स्थिति तो इस बार अत्यधिक दयनीय रही ह। इस बार भी कांग्रेस एक भी सीट प्राप्त नहीं कर सको है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीत का रहस्य क्या है?

दिल्ली विधान सभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक प्रचार के विषय में अधिक सकारात्मकता का प्रयोग किया है। आम आदमी पार्टी ने इस बार नकारात्मक प्रचार नहीं करने की रणनीति अपनाई, न तो पार्टी ने किसी के विरूद्ध भड़काऊ भाषण दिए न ही विरोधियों पर अनावयश्क प्रहार किया। पार्टी के नेताओं ने पूरे प्रचार के अतंर्गत पार्टी के पांच वर्ष में किए कार्य ही लोगों के सामने रखे। विरोधियों के बारे में न तो भडकाऊ भाषण दिए और न ही दुष्प्रचार का सहारा लिया। वहीं, इसके विपरित भारतीय जनता दल के नेताओं पर भड़काऊ भाषणबाजी करने एवं विरोधियों के विरूद्ध दुष्प्रचार करने के आरोप लगे। अरविन्द केजरीवाल ने बार–बार अपने आप को दिल्ली का बेटा बताया।

दिल्ली में उन्हें भाजपा नेता प्रवेश वर्मा, तजिंदर पाल सिंह बग्गा और कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल का आतंकवादी कहा। इसको लेकर चुनावों के अतंर्गत बार–बार लोगों से पूछा गया कि क्या मैं आतंकवादी हूं। यही कारण है कि इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा सख्ती दिखाई गई और ऐसा बोलने वालों को प्रतिबंधित किया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि 8 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। ऐसा करने पर आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया। यही कारण है कि कपिल मिश्रा पर दो दिन के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया।

आम आदमी पार्टी ने इस बार सकारात्मक प्रचार के अलावा एक और सतर्कता का ध्यान रखा, जिसके अतंर्गत पार्टी ने पूरे प्रचार के अतंर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा कि किसी भी प्रकार से सीधे पी.एम. नरेन्द्र मोदी से टकराव की स्थिति न बने। पार्टी ने न तो पी.एम. नरेन्द्र मोदी को लक्ष्य बनाया और न ही उन के बारे में कोई गलत भाषणबाजी की। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के मतदाताओं से भी अपने समर्थन में मत देने की अपील कर डाली।

आम आदमी पार्टी ने इस बार पूरा चुनाव कार्य एवं विकास के मुद्दों पर लड़ा। अरविन्द केजरीवाल ने बिजली और पानी के मुद्दे को पूरी तरह भुनाने में सफल रहे। यहां तक कि उन्होंने काम के नाम पर मतदाताओं से मत डालने की प्रार्थना की एवं भविष्य में भी कार्य करने का आश्वासन दिया। वहीं, भाजपा ने अरविन्द केजरीवाल के इस कार्य के प्रति नकारात्मक छवि बनान की कोशिश की, जिसमें कि परिणाम से स्पष्ट है कि वे असफल रहे।

आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में एक और मुद्दे को प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, वो है कि केजरीवाल के सामने कौन? याद हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने भी चुनाव अभियान में इसी प्रकार से मतदाताओं को साधने की कोशिश की थी, तब भाजपा वाले सवाल करते थे कि नरेन्द्र मोदी के सामने कौन है और यहां विधान सभा चुनाव में अरविन्द केजरीवाल ने भी यही रणनीति अपनाई और पूछा कि भाजपा का सी.एम. उम्मीदवार कौन?. भाजपा वाले इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और मतदाताओं ने निश्चित कर लिया कि दिल्ली में तो केजरीवाल ही है।

अरविन्द केजरीवाल ने एक अन्य काम को प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, वो था बिजली, पानी के अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक। अधिकतर लोगों ने माना कि मोहल्ला क्लिनिक सफल आदर्श रहे हैं। आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के लोगों को इनसे बहुत लाभ मिला। यद्यपि, भाजपा ने आयुष्मान योजना, उज्जवला योजना एवं प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना आदि योजनाओं का नाम लेकर उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई।

दिल्ली विधान सभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय विषयों को छोड़कर राष्ट्रीय विषयों पर ध्यान केन्द्रित रखा। भाजपा नेता अपनी सभाओं में नागरिकता संशोधन कानून, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियों को

गिनाते रहे। भाजपा ने अवश्य ही स्थानीय विषयों को उठाया परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतओं द्वारा पूरे चुनाव अभियान में तीन तलाक, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक पंजिक, राष्ट्रीय विषय तथा राष्ट्रवाद जैसे विषय ही मुख्यतः रहे।

दिल्ली में निःशुल्क बिजली–पानी का मुद्दा हिट रहा। 2015 में सरकार बनने के पश्चात आम आदमी पार्टी ने 20 हजार लीटर निःशुल्क पानी देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनते ही इसे लागू किया। इसके अतिरिक्त दिल्ली में 2015 में सरकार बनने पर 200 यूनिट पर आधी आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ किया। इसके पश्चात अगस्त 2019 में 200 यूनिट पर पूरी आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ किया अर्थात 200 यूनिट तक पूरी बिजली निःशुल्क कर दी। इसके पश्चात आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड में आगामी पांच वर्ष तक 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का आश्वासन दिया है।

नवंबर 2019 में आप सरकार ने महिलाओं की बसों में यात्रा निःशुल्क कर दी, इससे कामकाजी महिलाओं और घरेलू महिलाओं को बड़ी सहायता मिली। इससे आप सरकार ने दिल्ली की पचास प्रतिशत जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई। इसके साथ ही बसों में मार्शल भी लगाए गए। इससे चुनावों में महिला सुरक्षा का विषय प्रभावित रहा। यही कारण है कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में भरपूर मत दिया है। दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में व्यापक तौर पर सुधार किया गया। इसके लिए दिल्ली के बजट का 25 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवटित किया गया। इससे दिल्ली में लगभग 20 हजार नए कमरों का निर्माण किया गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों की शुल्क वृद्धि पर रोक लगाई। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमें दिल्ली विधानसभा के चुनावों मे देखने को मिला।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधान सभा के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी मे टक्कर देखने को मिली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया, जिसमें मुख्यतः राष्ट्रहित, नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजिका आदि रहे। किंतु आम आदमी पार्टी ने स्थानीय विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया। जिससे यह चुनाव राष्ट्रीय विषय बनाम स्थानीय विषय में केन्द्रित हो गया।

♦♦♦♦♦

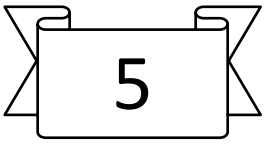

5

दिल्ली विधान सभा चुनाव 2020: विकास बनाम सांप्रदायिकता?

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव वर्तमान भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे से उत्पन्न हुए दल अर्थात आम आदमी पार्टी और भारतीय राजनीति के पटल पर प्रबलता से उभरी भारतीय जनता पार्टी के मध्य एक प्रत्यक्ष संघर्ष था। अधिकतम चुनावी विश्लेषण का उद्देश्य बड़े–बड़े आख्यानों को ढूंढ़ना होता है, परन्तु दिल्ली विधानसभा चुनावो में परिणाम की भांति आख्यान भी स्पष्ट थे। जिसे विकास बनाम साम्प्रदायिकता या राष्टवाद बनाम मुफ्तखोरी कहा गया। इस चुनाव के अंतर्गत लोगो के पास स्पष्ट मुद्दे थे एवं विकास, राष्ट्रवाद, साम्प्रदायिकता और मुफ्तखोरी जैसे आख्यानों तथा शब्दों को लोगों के समक्ष रखा गया था जिनमे उनको चुनाव करना था। जिनका प्रचार अधिकतम सोशल मीडिया पर किया गया।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में विकास की भूमिका

चुनावी रणनीतियों की दृष्टि से यदि दिल्ली विधानसभा चुनावों को देखा जाये तो सभी दलों द्वारा बहस के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया गया और राजनीतिक विशेषज्ञों ने इन मुद्दों को आख्यानों में परिवर्तित कर दिया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एवं अन्य विरोधी दलों द्वारा प्रारम्भ से ही इन चुनावों को विकास बनाम साम्प्रदायिकता के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया और भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहा वहीं भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी और अरविन्द केजरीवाल को झूठा बताया गया एवं इस चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम मुफ्तखोरी के ढांचे में डालने का प्रयास किया गया। परन्तु चुनावी परिणाम के पश्चात् यह देखने को मिलता है कि दिल्ली के मतदाताओं ने वास्तव में "विकास" के लिए मतदान किया था। जिसका पता विभिन्न समाचार चैनलों एवं शोध केन्द्रों द्वारा किये गए सर्वेक्षण से लगाया गया।

विभिन्न एग्जिट पोल ने सुझाव दिया कि दिल्ली के लिए वास्तविक मुद्दा नागरिकता संशोधन अधिनियम या हिन्दू–मुस्लिम मुद्दे न होकर विकास था। इंडिया टुडे–एक्सिस माई इंडिया एग्जिट

पोल में एक तिहाई से अधिक मतदाताआं ने कहा कि "विकास" उनका मुख्य विषय था, जबकि "राष्ट्रीय सुरक्षा" के मुद्दे को उनके सर्वेक्षण में 10 प्रतिशत से भी कम लोगो ने चयन किया। एबीपी–सीवीओटर एग्जिट पोल में, तीन बार मतदाताओं ने कहा कि वे "विकास" के लिए मतदान कर रहे थे।

विकास बनाम व्यक्तित्व

दिल्ली चुनावी परिणाम पूर्णतः विकास पर आधारित रहा, ऐसा कहना सही नहीं होगा क्योंकि यदि हम 2019 लाक सभा चुनावो के नतीजे देखें तो मतदाताओं द्वारा तब भी विकास को महत्ता दी गयी लेकिन परिणाम विपरीत थे। कुल मिलकर केवल विकास ही दिल्ली विधान सभा चुनाव के परिणाम का एकमात्र कारण था ऐसा कहना गलत है। वास्तविकता में अंतर मतदाताओं के मुद्दों में नहीं अपितु उनके द्वारा समर्थित नेता में था। जहाँ एक ओर दिल्ली विधान सभा चुनाव में बहुतायत लोगो का समर्थन आप पार्टी विशेष न हो कर अरविन्द केजरीवाल के समर्थन में था वहीं दूसरी ओर 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के समर्थन में मतदाताओं ने वोट किया था। कुल मिलाकर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भाजपा के लिए दिल्ली में समर्थन कमजोर था, लेकिन पीएम मोदी के लिए मजबूत था। यही तर्क संभवतः आप पर भी लागू हो सकता है। भारतीय राजनीति में यह पहली बार नहीं है कि व्यक्तित्व को महत्ता दी गयी हो ऐसा पहले भी होता रहा है।

साम्प्रदायिकता एवं हिन्दू–मुस्लिम राजनीति

भाजपा को 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2015 से अधिक वोट मिले इस तथ्य को भी नाकारा नहीं जा सकता है जिसम अधिकतम वोट उच्च–हिन्दू वर्ग (50 प्रतिशत) के होते हैं। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि आप को दिल्ली चुनाव में हिन्दू व् मुसलमान दोनों के वोट प्राप्त हुए हैं तो वोटों के आधार पर यह चुनाव हिन्दू–मुस्लिम राजनीति को नहीं दर्शातें हैं परन्तु जब मुस्लिम मतदाताओं से इंडिया टुडे ने एक्सिस माई इंडिया के द्वारा आप के पक्ष में मतदान करने का कारण पूछा, तो उन्होंने इसे भाजपा के विरुद्ध अपनी जीत के कारण बताया। दूसरे शब्दों में, दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं ने आप को वोट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा को हरान के लिए यही बेहतर विकल्प है। लेकिन चुनाव पूर्व यदि चुनावी रणनीति को देखा जाये तो इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम की भूमिका अहम् रही है। जिसमे भाजपा द्वारा पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान एवं बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यक व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गयी। जिसके साथ ही असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.

आर. सी.) लागू किया गया, जिसका पूरा लाभ दिल्ली चुनावो में विपक्ष ने उठाया और एंटी–सीएए प्रोटेस्ट को भाजपा के विरुद्ध प्रयोग किया जिसके अंतर्गत भाजपा को सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी बताया गया। इसी के साथ भाजपा द्वारा भी शाहीन बाग़ विरोध को लेकर आप सरकार की आलोचना की गयी। साथ ही अपने हिन्दू वोट के विचार और सीएए को राष्ट्रहित में बताते हुए राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया हालाँकि चुनाव प्रचार के दौरान कुछ भाजपा नेताओं द्वारा सांप्रदायिक कथन कहे गए जिसका नकारात्मक प्रभाव दिल्ली चुनाव में भाजपा को देखना पड़ा। जिससे यह चुनाव हिन्दू–मुस्लिम मुद्दे में ढल गया।

राष्ट्रवाद बनाम अभिशासन

यह चुनाव एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे और वह थी आप सरकार की अभिशासन की राजनीति, राजनीति इसलिए क्योंकि आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी मुलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिसके लिए पैसे की आवश्यकता भी बढ़ जाती है परन्तु आप पार्टी ने दिल्ली के लोगों की मुलभुत सुविधाएं मुख्यतः बिजली एवं जल पर भारी अनुवृत्ति दी जिस कारण लोगों के मुलभूत व्यय कम हो गये। इसी के साथ चुनाव से पूर्व आप पार्टी द्वारा बसों में महिलाओं की यातायात को निःशुल्क किया गया जिसका सकारात्मक प्रभाव चुनाव में आप के वोट प्रतिशत पर पड़ा और प्रत्यक्ष रूप से यही आम आदमी पार्टी की रणनीति रही है जिसका विकल्प भाजपा ने राष्ट्रवाद में खोजने का प्रयास किया। जिसमे भाजपा को हार का सामना करना पड़ा परन्तु यहाँ पूर्णतः असफलता नहीं कही जा सकती है क्योंकि 2015 की तुलना में भाजपा ने 2020 में अधिक सीटें एवं वोट प्रतिशत प्राप्त किया है।

कुल मिलाकर यदि हम देखें कि दिल्ली के लोगो ने वास्तव में किसके लिए मतदान किया है तो भारत में मतदाता वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं, अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व ही अपने मन बना लेते हैं, और व्यक्तिगत राजनीतिक नेताओं के व्यक्तित्व द्वारा पहले से कहीं अधिक उत्साहित होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपने जीवन में भौतिक सुधार चाहते हैं, जिसका कारण दिल्ली में रह रहे लोगो को अरविन्द केजरीवाल द्वारा दी जा रही सस्ती बिजली या पानी तथा बस सेवा है। लेकिन वैचारिक संकेत–चाहे वह अधिक हो या निहित–नेताओं और पार्टियों द्वारा वे वोट देते हैं।

♦♦♦♦♦

6

दिल्ली विधान सभा चुनाव, 2020: एक नारीवादी विश्लेषण

मधु झा

सहायक प्रोफेसर, लक्ष्मी बाई महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में संपन्न चुनाव में आम आदमी दल ने पुनः भारी बहुमत प्राप्त एक नए राजनीतिक वातावरण का आगमन किया है। भारत में पिछले 10 वर्षों में राजनैतिक इतिहास को देखें तो यह अवश्य प्रमाणित होता है, कि 'सामाजिक दबाव' आज के समय में हमारी राजनीतिक दिशा को काफी हद तक तय करती है। अरविंद केजरीवाल की शानदार जीत (70 में से 62 सीटों पर आम आदमी की जीत) ने आम जनता को एवं विशषकर सामाजिक विद्वानों को इस जीत के विश्लेषण एवं समीक्षा के लिए नए आयाम प्रदान किए हैं।

इस पेपर के द्वारा मैंने एक ऐसे ही महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी के दिल्ली चुनाव पर असर का विश्लेषण करने का प्रयास किया है और वह है जनसांख्यिकी महिलाएं। चुनाव में महिलाओं की सहभागिता एवं उनके प्रभाव का विश्लेषण करना आज के समय में अधिक महत्वपूर्ण है। इस चुनाव की विशेषता यह रही है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरों से बाहर आई और अपने मत का प्रयोग किया। पुरुष एवं महिला मतदाताओं के बीच के अंतर को भी इस चुनाव में मात्र 0.07 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। जहां पूर्ण मतगणना 62.59 प्रतिशत थी वही 62.55 महिलाओं ने मत डाल कर अपने नागरिकता के सर्वप्रथम कर्तव्य का निर्वाहन किया है।

2015 के चुनाव की अपेक्षा 6.1 प्रतिशत अधिक महिलाओं ने अपनी राजनीतिक भागीदारी का प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 लाख महिला मतदाताओं की वृद्धि हुई। अगर हम महिला चुनावी प्रत्याशियों की तरफ ध्यान दें तो पता चलता है कि आप, बीजेपी एवं कांग्रेस ने मात्र 24 महिलाओं का चुनाव में टिकट दिया था। 672 प्रत्याशियों में केवल 79 महिलाओं को चुनाव में लड़ने का अवसर मिला। यह बात ध्यान देने की है कि 2020 के विधानसभा चुनाव ने 11 प्रतिशत महिलाओं को चुनावी मैदान में लाकर महिला प्रत्याशियों का सबसे बड़ा आंकड़ा इस चुनाव ने प्रस्तुत किया है। इन 79 महिलाओं में केवल 8 महिलाओं को सफलता प्राप्त हुई और वह सब आम आदमी पार्टी की थी।

इन सब आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के पीछे महिलाओं का भी एक विशेष एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ अध्ययनों की माने ता महिला मतदाताओं को इस जीत का सबसे बड़ा कारण भी बताया जा रहा है। विचार करने की बात यह है कि ऐसे क्या विशेष कारण हो सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन में आने को विवश किया ? क्या अरविंद केजरीवाल के कल्याणकारी राज्य के परिपेक्ष्य पर जोर ने महिलाओं को आकर्षित किया है? आम आदमी पार्टी के अध्ययन से यह साफ पता चलता है कि इस पार्टी ने प्रारंभ से ही महिलाओं को एक सक्रिय वोट बैंक की तरह देखा है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध जैसे मुद्दे पर जिस पार्टी की नींव रखी गई हो उसे महिला जैसे संवेदनशील वोट बैंक से समर्थन मिलना तो साधारण सी बात है। अन्य पार्टियों के अपेक्षा, इस नए पार्टी ने उदारवाद के उपरांत बदलते भारत की छवि को ना ही सही प्रकार से पहचाना है बल्कि उसे सही दिशा भी दिखलाई है।

दिल्ली राजधानी में जहां पड़ोसी राज्यों की काफी जनसंख्या रोजगार एवं शिक्षा के बेहतर अवसरों के लिए आसरा लेने आते हैं वही मुफ्त बिजली, इलाज, एवं रियायती दर पर शिक्षा ने महिलाओं पर इसका विशेष असर किया है। पिछले सालों (2014–15 से 2018–19) के दिल्ली सरकार के जेंडर बजट पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि दिल्ली और कुछ राज्यों में से है जिसने केंद्रीय सरकार की लिंग आधारित बजट के दिशा निर्देशों को लागू किया है। हैरानी की बात है पिछले चार–पांच सालों में दिल्ली का जेंडर बजट केंद्रीय सरकार के जेंडर बजट से भी अधिक रहा है। टिप टॉप ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केजरीवाल सरकार ने विशेष ध्यान देकर महिलाओं को काफी लाभान्वित किया है। यह वे मुद्दे हैं जिन से महिलाओं की जिंदगी काफी गंभीर रूप से जुड़ी हुई है।

परिवहन एवं महिला सुरक्षा

दिल्ली को हम कई बार अपराधी राजधानी के नाम से भी संबोधित करते हैं और इसी कारण से महिलाएं यहां काफी असुरक्षित एवं लाचार महसूस करती है। सार्वजनिक परिवहन को सस्ता एवं सुरक्षित बनाना केजरीवाल सरकार की सफलता का एक ऐसा उदाहरण है जिससे महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुई है। इस नीति को अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया जिससे महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा करने को मिला। सरकार ने करीब 428 नइ बसों का ऐलान किया जिनमें महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे एवं पैनिक बटन के प्रावधान भी थे। पूरे दिल्ली शहर में 1.3 लाख सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। इन सब का प्रभाव यह रहा कि महिलाओं ने

इस पार्टी के कार्यक्रमों को सराहा और सक्रिय रूप से केजरीवाल के समर्थन में चुनावी प्रचार में भी नजर आई।

शिक्षा

महिलाओं के लिए उनके बच्चों की शिक्षा हमेशा से उनकी प्रथम प्राथमिकता रही है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर प्रकार की मेहनत भी करने को तैयार रहती है। सरकार ने शिक्षा पर अपना बजट आवंटन 2013–14 में 18 प्रतिशत से 2019–20 में 26 प्रतिशत तक बढ़ाया, लोगों के बीच कैसे लोकप्रिय ना होती? इस सरकार ने ना केवल आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने का काम किया बल्कि नए विद्यालयों को खोलने का ऐलान भी किया। विद्यालयों में बेहतर आधारिक संरचना प्रदान करवाना एवं अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ने का भी काम इस सरकार ने जोर–शोर से किया है। निजी विद्यालयों में मनमाने तरीकों से जिस प्रकार हर वर्ष फीस बढ़ा करती थी, इस सरकार ने उस पर पिछले 4 सालों में रोक लगा दी है। मध्यमवर्गीय एवं निम्नवर्गीय महिलाओं के लिए बेहतर एवं सच्ची शिक्षा नीति ने अरविंद केजरीवाल को उनके बीच एक लोकप्रिय नेता बनाने में काफी सहायता की है।

स्वास्थ

मोहल्ला क्लीनिक, पाली क्लीनिक अस्पतालों पर केजरीवाल सरकार के कामों ने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को गरीबों एवं जरूरतमंदों तक पहुंचाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। 1.6 करोड़ मरीज जिन्होंने मोहल्ला क्लीनिक से इलाज करवाया उनमें 80 प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे हैं। मुफ्त दवाइयां एवं टेस्टों ने महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं जिंदगी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि नागरिकता संशोधन विधेयक विरोधी आंदोलन ने भी दिल्ली चुनाव पर अपना प्रभाव डाला है। शाहीन बाग में पिछले दो–तीन महीनों से चलते आंदोलन में महिलाओं ने बढ़–चढ़कर अहिंसक तरीकों से अपनी भागीदारी एवं नतृत्व दिखाया है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में मत देकर महिलाओं ने दिल्ली में समाजिक सुरक्षा एवं शांति को चुनने का एक प्रयास किया है। एक अच्छे राज्य की पहचान निसंदेह स्वस्थ एवं कुशल नागरिकों का होना है और अरविंद केजरीवाल ने कुछ अहम मुद्दों को मुख्यधारा में लाकर उदारवादी राज्य की समस्त चुनौतियों का डटकर मुकाबला ही नहीं किया बल्कि महिलाओं को विकास का भागीदार बना कर निष्कर्ष भी निकालने का प्रयास किया है।

♦♦♦♦♦

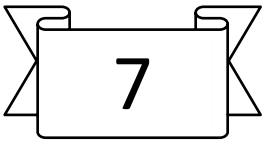

राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टीः राम बनाम हनुमान की राजनीति

जया ओझा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

शायरों के शब्दों में दिल्ली को 'हिंदुस्तान का दिल' कहा गया है। अब दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का दिल हो या न हो, परंतु राजनीति एवं प्रशासन का दिल अवश्य ही है। इसके चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच उत्साही प्रतिस्पर्धा को स्पष्टतः देखा जा सकता है। केवल सात सांसद एवं 70 विधायक चुनने वाली दिल्ली का भौगोलिक स्वरूप अत्यधिक बड़ा नहीं है जो देश की राजनीति या लोकसभा के स्वरूप को अधिक प्रभावित कर सके, परंतु दिल्ली की आबादी, उनके मत का रुझान तथा यहाँ का दलीय स्वरूप एवं उनकी विचारधारा भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 'हार्ड हिन्दुत्व' के विपरीत 'सॉफ्ट हिन्दुत्व' का प्रयोग किया गया, इसके अंतर्गत चुनावी रणनीति का एक नया स्वरूप देखा गया जो था 'बजरंगबली' (हनुमान) का उदय।

समकालीन समय की राजनीति में राजनेताओं द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए ईश्वर, धर्म तथा राष्ट्रवाद का सहारा निरंतर लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 'जय श्रीराम' की राजनीति 90 के दशक से ही करती आ रही है, परंतु दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह कारगर सिद्ध नहीं हुई। बापू राऊत (बहुजन विचारक) कहते हैं कि 'आप' का बजरंगबली 'भाजपा' के जय श्रीराम पर भारी पड़ गया। इस प्रकार आप ने दक्षिणपन्थियों के सिद्धांतों का प्रयोग करके भाजपा को परास्त कर दिया। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर अरविंद केजरीवाल के विशाल से चित्र के साथ लगे पोस्टर पर लिखा था 'राष्ट्र निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़े'। इससे यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से बाहर एक बार पुनः अपना आकार बढ़ाने कि ओर अग्रसर हो रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी का मुख्य कार्यवकारो (एजेंडा) मात्र मोदी–विरोधी नहीं है, जैसा कि 2013–14 में रहा, अपितु केजरीवाल इस समय कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मतदातों को लुभाने के लिए किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम स्पष्ट होने के बाद, केजरीवाल ने अपने

सम्बोधन का आरंभ 'भारत माता की जय' एवं 'वंदे मातरम' के राष्ट्रवादी नारे के साथ किया। यही नहीं उन्होने यह भी कहा की 'आज हनुमान जी का जन्मदिन है, उनकी कृपा बरस रही है। अतः केजरीवाल की रणनीति स्पष्ट देखी जा सकती है की वह भारतीय जनता पार्टी को उसी की विचारधारा पर चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं अर्थात यदि भारतीय जनता पार्टी 'जय श्रीराम' के भरोसे है तो आम आदमी पार्टी ने 'हनुमान जी' पर भरोसा कर लिया है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या आम आदमी पार्टी यह मार्ग अपना कर, भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त दल को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे पाएगी? इस प्रश्न का उत्तर तो आने वाला समय ही दे पाएगा।

अरविंद केजरीवाल के इंडिया अगेन्स्ट करप्शन आंदोलन के समय एवं बाद में दल में भी रहे उनक सहयोगी का मानना है कि "केजरीवाल तो अपनी पुस्तक स्वराज्य में भी यह कहते हैं कि वे कभी मंत्री तक नहीं बनेंगे, परंतु आज वो एक मुख्यमंत्री हैं। वे 2013–14 में प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे थे, परंतु पंजाब व गोवा के परिणामों ने उनकी अपनी सीमाएं बता दी....अब वो पुनः चुनाव में विजय हुए हैं, ऐसे में वे पुनः अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। परंतु ऐसा करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसके दो मुख्य कारण हैं– पहला, वह किसी अन्य नेता को उभरने का अवसर नहीं देते हैं, दूसरा, यह दल संगठनात्मक रूप से दिल्ली के बाहर बहुत ही निर्बल है।" (आउटलुक, 9 मार्च,2020० पृ० 16–17)

पार्टी की इस नई रणनीति पर आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय कहते हैं कि "हम सकारात्मक राष्ट्रवाद की तुलना कर रहें हैं, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के घृणास्पद राजनीति को समझ लगो है। इसलिए सर्वप्रथम हमें देश के दूसरे क्षेत्रों में संगठन को सुदृढ़ करना है। देश भर के पदाधिकारियों के बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि पार्टी 'राष्ट्र निर्माण अभियान' 23 फरवरी से 23 मार्च तक चलाएगी। इससे एक करोड़ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 'आप' ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों के उत्कृष्ठ जीवन पर ध्यान केन्द्रित किया जिसका परिणाम दिल्ली विधान सभा चुनाव 2020 के विजय के रूप में देखा जा सकता है, वही अब पूरा देश चाहता है।"

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक तथा आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित रह चुके आनंद कुमार का कहना है कि "किसी भी राजनैतिक पहल को राष्ट्रीय आकार लेन के लिए उसमें नई बात का होना अनिवाय है। आम आदमी पार्टी के समय सुशासन की मांग थी, उन परिस्थितियों में हमने एक वैकल्पिक राजनीति का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। परंतु पिछले 6 साल में केजरीवाल ने 'वैकल्पिक राजनीति' के बजाय 'वैकल्पिक व्यक्तित्व'

को हथियार बनाया है, जिसके अंतर्गत 'न खाता न बही जो केजरीवाल कहें वही सही।' ऐसी राजनीति से आप क्षेत्रीय स्तर पर तो अवश्य सफल हो सकते हैं, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करना संभव नहीं है।"

भले ही केजरीवाल ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त की है, परंतु पार्टी का जनाधार दूसरे राज्यों में पिछले पाँच सालों में कमजोर हुआ है। इसके साथ ही इनके पास संगठन भी न के बराबर ही है। पिछले कुछ सालों में पार्टी को छोड़कर जाने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। किसी भी दल का आधार उसका संगठन होता है, राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए 'आप' को देश की समस्याओं की ओर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय विषयों पर आम आदमी पार्टी का दृष्टिकोण बहुत ही भ्रांतिपूर्ण रहा है। उदाहरणतः एक ओर वह सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़े करने लगे है तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनुच्छद 370 के समापन का समर्थन भी किया। शाहीन बाग के विषय पर उन्होने अंतिम समय तक चुप्पी साधी रही और इससे दूरी बनाने लगे। परंतु अब इन विषयों पर उन्हें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना होगा, क्योंकि दिल्ली में तो उन्होने बिजली–पानी से परेशान लोगों को उसका समाधान दे दिया, परंतु देश में बेरोजगारी, कृषि समस्या, आरक्षण, सांप्रदायिकता की राजनीति का समाधान रखना होगा। इसके साथ ही उन्हें 543 सीटों वाली लोकसभा के लिए देश भर में मजबूत उम्मीदवार की भी अवश्यकता है तभी कुछ किया जा सकता है।

यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा की राम एवं हनुमान की राजनीति में किसकी विजय होती है। केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा में एकला चलो की रणनीति काम आती है या फिर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन काम आता है। हो सकता है की दिल्ली में केजरीवाल के हनुमान जी की राजनीति काम आ गयी हो, परंतु क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करेगा यह प्रश्न 2024 तक बना रहेगा जब तक कि 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते। भारतीय राजनीति को इस समय एक वैकल्पिक राजनीति की अवश्यकता है, परंतु विकल्प बनने के लिए अरविंद केजरीवाल को अपने दोषों को दूर करना अनिवार्य है।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007